भिक्षावृत्ति एवं कचरा बीनने में बीत रहा बचपन, कहां गई शासन की पुनर्वास नीति

नवभारत न्यूज

पन्ना, 1 सितंबर। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिये पुनर्वास नीति बनाई थी। जिसमें प्रावधान किया गया था कि भिक्षावृत्ति करने वाले, कूड़ा व पन्नी बीनने वाले, श्रम करने, गरीबी और अन्य विपरीत परिस्थितियों के कारण सड़क में रहने वाले बच्चों का सुदृढीकरण किया जायेगा। उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभन्वित कर बच्चों का संरक्षण, भरण पोषण एवं समग्र पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी।

उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जायेगा। किन्तु इस नीति के प्रभावी होने के बाद सड़कों में जीवन यापन करने वाले बच्चों में कोई कमी दिखाई नहीं देती। पता ही शासन की यह योजना किस लोक में संचालित हो रही है और इस योजना के नाम पर क्या-क्या खानापूर्ति की जा रही है।

इस तरह ये उद्येश्य:- इस नीति को लागू करने के लिये जो उद्येश्य थे उसमें कहा गया था कि सड़क में जीवन यापन करने वाले बच्चों का चिन्हांकन किया जायेगा। उनका अभिलेखीकरण किया जायेगा। उन बच्चों को देखभाव व सुरक्षा की जायेगी। इसके लिये विधिवत कार्ययोजना तैयार की जायेगी। मुख्य धारा से जोड़कर उनका सर्वागीण विकास किया जायेगा। जीवनोपयोगी सुविधायें दी जायेंगी, उनकी पहचान कर पुनर्वास की व्यवस्था होगी, पुनर्वास के लिये

उचित मानीटरिंग भी होगी, विभागों की भूमिका सुनिश्चित की जायेगी, पुनर्वास के लिये कार्ययोजना तैयार की जायेगी। किन्तु जब से इस नीति का लागू किया गया है तब से अब तक में कितने बच्चो को चिन्हित किया गया। कितने बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। उन्हें कहां रखा जाता है कौन सा स्थान सुनिश्चित किया गया है। मानीटरिंग कौन लोग कर रहे हैं और कार्ययोजना के अनुसार क्या क्या गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। यह सब केवल औपचारिकता मात्र ही समझ में आ रहा है।

नीति में तो बहुत कुछ शामिल किन्तु जमीन में कितना हुआ?:- सवाल तो यह है कि सड़क में रहने वाले बच्चों के लिये नीति 2022 तो बना दी गई किन्तु उसका क्रियान्वयन कितना हुआ। शासन की तरफसे इस नीति को लागू करने के लिये बजट प्रावधान कितना किया गया और बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिये किस स्तर तक प्रयास हुये। कितने बच्चो का पुनर्वास किया गया। इसकी कोई जानकारी अभी तक प्रकाश में नही आई। कागजों में खानापूर्ति के लिये हो सकता है कि बहुत कुछ दिखाया जा चुका हो। किन्तु जिस तरह से जगह बाल श्रमिक काम करते हुये दिखाई देते हैं, जिस तरह से भीख मांगते हुये और कचरों के ढेर में पन्नी व प्लास्टिक आदि को बीनते हुये बच्चे दिखाई देते हैं उसको देखते हुये ऐसा नही लगता कि उन बच्चो की पहचान की गई होगी और उनके परिवारों को समझाया गया होगा अन्यथा कुछ न कुछ तो सुधार होता दिखाई देता। कई ऐसे बच्चे भी दिखाई देते हैं तो बीड़ी, सिगरेट फूकते रहते हैं। सामाजिक रूप से देखा जाय तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी है जहां संबंधित विभागो को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिये। किन्त दुर्भाग्य का विषय यही है कि जब कोई योजना फाईलों तक सीमित हो जाती है तो वह केवल दिखाने के लिये होती है, वह केवल जनता को मूर्ख बनाने और भ्रमित करने तक ही सीमित रह जाती है।

कहां है बाल कल्याण समिति ?

नीति के अनुसार ऐसे बच्चों की जानकारी बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी। बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बच्चो के परिवारों से एक बंधपत्र लिया जाना था। जिसमें उन्हें स्कूल भेजने, परिवार में रखने, नशा न करने आदि का परामर्श भी शामिल किया गया था। चिन्हांकित एवं रेस्क्यू किये गये बच्चो की स्वास्थ्य जांच, परामर्श, चिकित्सीय उपचार आदि के उपरान्त बाल कल्याण समिति द्वारा उन्हें बाल देखरेश संस्था या नशामुक्ति केन्द्र में भी रखने का आदेश दे सकती थी। बाल कल्याण समिति को यह अधिकार भी दिये गये थे कि वह संरक्षण में रखे गये बच्चों की स्थिति एवं परिस्थति के अनुसार बाल देखरेख योजना एवं उनकी केस हिस्ट्री भी तैयार करवा सकती थी। किन्तु यह सब प्रावधान होने के बाद यहां इस मामले में कितना कार्य हुये यह अज्ञात के अंधेरे में चल रहा है।

लक्ष्य समूह के अनुसार कितने बच्चे चिन्हित

नीति के अनुसार बच्चों को चिन्हित करने के लिये लक्ष्य समूह निर्धारित किये गये थे। जहां बिना किसी सहयोग के अकेल रहने वाले बच्चों का समूह, ऐसे बच्चे जा दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के साथ सड़क में रहने वाले बच्चे, प्रवासी परिवार के बच्चे, परित्यक्त बच्चे, दिव्यांग बच्चे, निराश्रित बच्चे, बाल श्रमिक, कामकाजी बच्चे, बाल भिक्षुक, कामकाजी या कचरा पन्नी बीनने वाले बच्चों का समूह निर्धारित किया गया था। जहां पहचान के अनुसार बच्चों को सूचीबद्ध किया जाना था। किन्तु ऐसा नहीं लगता कि इस जिले मे इतनी बड़ी एक्सरसाईज अभी तक हुई होगी जिससे बच्चों की पहचान की गई होगी। यही कारण है कि आज भी सड़कों पर कई ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो भीख मांगने का कार्य करते हैं। कई जगह तो धर्म स्थलों में ऐस बच्चे नारियल फोड़ने से लेकर तिलक लगाने तक का कार्य करते हुये देखे जाते हैं।

सर्वे, चिन्हांकन एवं रेस्क्यू आदि का था प्रावधान

नीति के अनुसार ऐसे बच्चों की ग्रामीण, शहरी, कस्बाई नगर पंचायत और नगर पालिका सहित सभी क्षेत्रों में पहचान की जानी थी। उनके चिन्हाकन के लिये सर्वेक्षण किया जाना था। सर्वे दलों का गठन किया जाना था। विभिन्न शासकीय विभागों सहित सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया जाना था। प्रमुख धार्मिक स्थलों, पर्यटन, एतिहासिक स्थलों के लिये विशेष दलों का गठन किया जाना था। ऐसे हाट स्पाट एवं आशंकाग्रस्थ स्थलों का चिन्हाकन किया जाना था जहां अधिक संख्या में सड़कों में बच्चे पाये जाने की स्थिति थी। यह जानकारी बाल स्वराज पोर्टल में दर्ज की जानी थी। डेटा तैयार होने के बाद ऐसे बच्चों के परिवारों को भी समझाईस देने का प्रावधान किया गया था। निराश्रित, परित्यक्त, शोषण के शिकार एवं बाल तस्करी में शामिल बच्चों का रेस्क्यू भी किया जाना था और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाना था। किन्तु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार चोरियों में ऐसे बच्चों के नाम भी प्रकाश में आते हैं जो कम आयु के होते हैं, जो गरीब होते हैं।

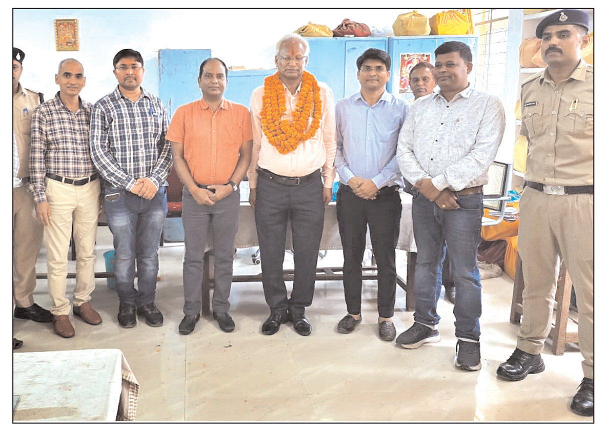

आबकारी आरक्षक सेवानिवृत हुए दी गई भावभीनी विदाई

नवभारत न्यूज

पन्ना, 1 सितंबर। आबकारी विभाग में पदस्थ आरक्षक देवघर शर्मा लगभग 37 वर्ष 10 महीने की सेवा के पश्चात सेवा निवृत हो गए। इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पन्ना में उनकी सेवा निवृत्ति पर विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आबकारी अधिकारी जिला पन्ना मुकेश कुमार मौर्य ने उनकी कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव ने श्री शर्मा की ईमानदारी को याद किया। आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय ने श्री शर्मा की अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण की जानकारी दी। आबकारी उपनिरीक्षक हरीश पाण्डेय और विक्रांत जैन ने उनके अनुभवों और सहयोगियों के मार्गदर्शन के अनुभव सुनाते। मुख्य लिपिक नाथूराम सौर ने उनके अच्छे भविष्य और स्वास्थ्य के लिए कामना की।

इस अवसर पर अरुण चौरसिया, ऋ षिकांत सोनी, रजनीश खरे, अशोक पाण्डेय, प्रीतम नायक, स्मिता ठाकुर, कुलदीप जाटव, रविप्रकाश मिश्रा, मोतीलाल प्रजापति, वीरेंद्र यादव, जहान सिंह, सोनू बुंदेला, आकाश साहू, धर्मेंद्र वाजपेई, सुरेश शिवहरे आदि उपस्थित रहे।

चार माह में 16 डॉक्टरों की हुई पोस्टिंग, 10 ने ज्वाइन नहीं किया

चार डॉक्टर ज्वाइन के बाद वापस नहीं आए

नवभारत न्यूज

पन्ना, 1 सितंबर। किसी भी जिले का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन सहित सडकों की स्थिति पर अधिकांशत: निर्भर करता है। पन्ना जिले का यह हाल है कि तीनों चीजों की कमी पन्ना जिले में है शिक्षा का यह हाल है कि न तो विद्यालयों में शिक्षक है और न ही कालेजों में सब अतिथि शिक्षकों के भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है।

यही हाल स्वास्थ्य विभाग का है जिले में स्वीकृत डॉक्टरों की संख्या से आधे डॉक्टर भी पदस्थ नहीं है और न ही कोई पन्ना आना चाहता है। विगत चार माह के अंदर लगभग 16 डॉक्टरों की पदस्थापना पन्ना में हुई। इनमें 10 चिकित्सकों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। जिन चार चिकित्सकों ने ज्वाइन किया वे ज्वाइन करने के बाद गये तो दोबारा लौटकर ही नहीं आए। चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल प्रबंधन भी परेशान है। इन सभी 16 चिकित्सकों की पदस्थापना किसी गांव-कस्बे के अस्पताल में नहीं जिला अस्पताल में हुई थी। इसके बाद भी अधिकांश चिकित्सकों ने ज्वाइन ही नहीं किया। जिला अस्पताल में मेडिकल ऑफीसर के 21 और विशेषज्ञों के 30 कुल 51 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कार्यरत केवल 21 चिकित्सक हैं। मेडिकल ऑफीसर के 16 और विशेषज्ञ चिकित्सकों के 15 पद सालों से खाली हैं।

अंचल के अस्पतालों का भी यही हाल:- जिलेभर में डाक्टरों के 122 से अधिक पद स्वीकृत हैं लेकिन पचास फीसदी से अधिक चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं। जिले की जनसंख्या करीब 14 लाख है लेकिन सिर्फ 44 चिकित्सक (निजी संस्थानों को छोड़कर) पदस्थ हैं। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार करीब 600 व्यक्ति पर एक डाक्टर होना चाहिए।

सीएचसी में विशेषज्ञों के पद खाली:- जिला अस्पताल सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। सीएचसी पवई को छोड़कर सभी केंद्रों में भी विशेषज्ञ सहि चिकित्सक नहीं हैं। लोगों मजबूरी में नीम-हकीमों के पास जा रहे हैं या फिर निजि चिकित्सा संस्थानों के चक्कर काट रहे हैं। लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही हैं।

इन डॉक्टरों की हुई थी पदस्थापना:- डॉ मंजिल, डॉ प्रांत गुप्ता, डॉ शिवांगी शाही, डॉ अंजली सिंह, डॉ शुचिस्मिता दत्ता, . डॉ महेंद्र सिंह भदौरिया, डॉ प्रियंका सिंह, डॉ श्रुति अग्रवाल, , डॉ शुरभि शाक्या, डॉ प्रहलाद कोरी, डॉ आयुष शुक्ला, डॉ रॉबिन राठौर, डॉ शुरभि राठौर, डॉ अश्वनी मेड़ा, डॉ पूजा इंगल, डॉ अंजली दुबे की पदस्थाना हुई थी।

एमएलसी को नहीं मिल रहे चिकित्सक:- जिला अस्पताल में पोस्ट मार्टम, एमएलसी, आकस्मिक ड्यूटी के लिए डाक्टर नहीं मिल पा रहे है। महिला मेडिकल ऑफीसर नहीं होने से पीड़िताओं को एमएलसी के लिए दूसरे जिले छतरपुर भेजा जा रहा था। इससे पीड़िताओं समेत परिजनों को भटकाव का सामना करना पड़ रहा है।

7 पीएचसी वार्ड ब्यॉय के भरोसे

जिले के 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन हैं। इन स्वास्थ्य केन्द्रों को वार्ड ब्यॉय व स्टाफनर्स के भरोस चलाया जा रहा है। जिनमें वर्षों से डाक्टरों की पदस्थापना नहीं की गई है। स्टाफ की कमी के चलते संचालनालय से भेजी गईं जांच मशीनें सहित अन्य उपकरण बंद पड़े हुए हैं। जिनका लाभ रोगियों को नहीं मिल पा रहा है।

पांच को अमानगंज आएंगे सीएम डॉ .मोहन

महिला सम्मेलन सहित विकास कार्यों की देंगे सौगात

नवभारत न्यूज

पन्ना, 1 सितंबर। कलेक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगामी 5 सितम्बर को गुनौर विधानसभा के अमानगंज आगमन के संबंध में अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दोपहर 2 बजे महिला सम्मेलन के कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन तथा अन्य कार्यक्रमों में शामिल होना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नगर परिषद अमानगंज में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए जिला पंचायत सीईओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य विभागीय अधिकारियों को भी आवश्यक दायित्व सौंपा जाएगा। कलेक्टर श्री कुमार ने मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत बैठक व्यवस्था, संचार, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग एवं यातायात, रूट चार्ट, लायजनिंग अधिकारी की नियुक्ति, ग्रीन रूम की स्थापना इत्यादि व्यवस्थाओं के संबंध में समय सीमा में जरूरी समन्वय के साथ पूर्व तैयारी के निर्देश दिए। इसके अलावा जल जीवन मिशन एवं केन-बेतवा लिंक परियोजना पर केन्द्रित प्रदर्शनी भी कार्यक्रम स्थल पर लगाने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आजीविका मिशन, कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा वन विभाग के अधिकारियों को भी विभागीय योजनाओं पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा आरटीओ सहित खाद्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के साथ अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा। इस क्रम में प्रारंभिक तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने टीएल बैठक में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के आठ चयनित विषयों सहित 100 दिवस से सहित समयावधि के लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण एवं प्रगति की समीक्षा कर समय सीमा में शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का पात्र हितग्राहियों को मिले लाभ:- कलेक्टर ने कहा कि सभी नगरीय निकायों के सीएमओ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रगति की मॉनिटरिंग कर आवास योजना 2.0 का पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ प्रदान करें। आवास का निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण हो। प्रत्येक नगरीय निकाय हितग्राहियों के सत्यापन कार्य में गति लाना सुनिश्चित करें. ।

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को एसपी की अध्यक्षता में दी गई भावभीनी विदाई

नवभारत न्यूज

पन्ना 1 सितंबर। जिला पुलिस बल पन्ना में सेवाएँ दे रहे 3 पुलिस अधिकारी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पन्ना साईं कृष्ण एस. थोटा की अध्यक्षता में पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल पन्ना में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं को भावभीनी विदाई दी गई।

सेवानिवृत्त अधिकारियों में उप निरीक्षक विष्णु दत्त चतुर्वेदी, जो कि वर्तमान मे थाना पवई मे अपनी सेवायें दे रहे थें। जिनकी मध्यप्रदेश पुलिस विभाग मे सेवा 43 वर्ष की सेवा अवधि रही। सहायक उप निरीक्षक मोहन पांडेय, जो कि वर्तमान मे पुलिस लाइन पन्ना मे पदस्थ थे। इन्होने मध्यप्रदेश पुलिस विभाग मे 44 वर्ष तक अपनी सेवायें दी। सहायक उप निरीक्षक मान सिंह ठाकुर, जो कि वर्तमान मे थाना कोतवाली पन्ना मे अपनी सेवाये दे रहें थे। इन्होने लगभग 43 वर्ष तक पुलिस विभाग को अपनी सेवाये दी। इन तीनों अधिकारियों ने अपने लंबे सेवाकाल में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए पुलिस विभाग को अपनी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता से गौरवान्वित किया। समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक पन्ना ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को शाल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, पुलिस स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट कर उनकी दीर्घकालीन सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधिकारीगणों द्वारा निभाई गई सेवाएँ पुलिस बल की धरोहर हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेंगी। पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को मंगलमय जीवन, उत्तम स्वास्थ्य एवं उनके परिजनों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भी अपने लंबे सेवाकाल के अनुभव साझा किए। उन्होंने सेवा के दौरान आए विभिन्न अनुभवों और चुनौतियों पर चर्चा की, जिससे उपस्थित जूनियर पुलिस कर्मचारियों को प्रेरणा एवं सीख प्राप्त हुई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री वन्दना चौहान, रक्षित निरीक्षक खिलावन सिंह कंवर, यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक नीलम लक्ष्यकार, थाना प्रभारी कोतवाली रोहित मिश्रा, सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिजन, तथा बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

खाद के लिए हजारों किसानों की लगी लाइन

एसडीएम पुलिस की मौजूदगी में बटी खाद, विधायक ने देखी किसानों की दुर्दशा

नवभारत न्यूज

गुनौर/पन्ना 1 सितंबर। वर्तमान में गुनौर क्षेत्र खाद की समस्या से जूझ रहा है आज मंडी प्रांगण की खाद गोदाम में हजारों लोगों की लाइन में खड़े होकर दो बोरी खाद लेने के लिए किसान लाइन में लगे देखे गए। उसके बाद भी अंत में कई किसानों को दो बोरी खाद की पर्ची भी नहीं मिल पाई।

इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गुनौर एवं सलेहा थाना प्रभारी अपने बल के साथ मौजूद रहे एसडीएम तहसीलदार ने स्वयं उपस्थित रहकर किसानों को खाद की पर्चिया बटवायी। खाद की समस्या से जूझ रहे किसानों की दुर्दशा को सुनकर गुनौर विधायक राजेश वर्मा

भी मौके पर पहुंचे उन्होंने खाद वितरण की व्यवस्था देखकर नाराजगी व्यक्त की एवं मौके पर उपस्थित तहसीलदार मेडम को खाद वितरण की व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दिया कहा कि जिसके पास पट्टा है उसी को खाद दें बाकी अन्य को नहीं एवं ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो खाद की पर्ची लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं। मौके पर एसडीओपी मानसिंह ने भी उपस्थित रहकर भीड़ को नियंत्रित करते देखे गए। खाद वितरण के समय ऐसे शासकीय कर्मचारी जो अपनी नौकरी ना करके खेती एवं अन्य व्यापार में संलग्न रहते हैं वह भी कार्यालय समय में खाद के लिए प्रांगण में खड़े देखे गए इन्हीं भ्रष्टाचारियों के कारण वास्तविक जरूरत मंदों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

वहीं दूसरी तरफकिसानों की खाद एवं अन्य समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम गुनौर को कांग्रेस पार्टी ब्लॉक गुनौर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा जिसे एसडीएम गुनौर के उपस्थिति न रहने पर नायब तहसीलदार राजेश मेहरा ने रिसीव किया।

पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार नहीं हुई कोई कार्यवाही

चार बार की गई शिकायत

नवभारत न्यूज

पन्ना ,1 सितंबर। जिला मुख्यालय मे जनसुनवाई के दौरान गुनौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटना तमोली के उपसरपंच राजू चौरसिया द्वारा जुलाई अगस्त दो माह के दौरान चार बार शिकायत की लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उप सरपंच ने दिये गये शिकायत पत्र में सरपंच एवं सरपंच, सचिव एवं उपयंत्री पर आरोप लगाया था कि पंचायत द्वारा बफराई तलैया जीर्णोद्धार के नाम पर 2 लाख 19 हजार 500 रूपये बिना किसी कार्य के फर्जी तौर पर निकाल लिये। साथ ही पंचायत मे आरसीसी, रोड, नाली निर्माण आदि कार्यो में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है।

उनके द्वारा पंचायत सचिव के पास आय व्यय की जानकारी हेतु आवेदन लगाया लेकिन सचिव द्वारा आज तक इसकी जानकारी नहीं दी गई। उपसरपंच ने जिला प्रशासन से अपेक्षा की है कि दिये गये आवेदन की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

जिला स्तरीय खेलकूद आवंटन बैठक का हुआ आयोजन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 1 सितंबर। आज दिनांक 1 सितंबर को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एस.डी. चतुर्वेदी की अध्यक्षता एवं पन्ना जिले के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं क्रीड़ा अधिकारीगण, क्रीड़ा प्रभारियों की उपस्थिति में सत्र 2025-26 के लिए जिला स्तरीय खेलकूद आवंटन बैठक का आयोजन प्राचार्य कक्ष में किया गया।

उक्त बैठक में आगामी सत्र हेतु बिंदुवार चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्णय लिए गए। सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस चतुर्वेदी द्वारा सभी से परिचय प्राप्त कर बैठक के बिंदुओं को संक्षेप में बताया एवं तदुपरांत जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय आयोजनों हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा संभाग स्तरीय बैडमिंटन (पुरुष) बास्केटबॉल (पुरुष) एवं कबड्डी (महिला) का आयोजन शासन से मांगा जाएगा तथा पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन संभाग स्तर पर शासकीय महाविद्यालय

अजयगढ़ द्वारा प्रस्तावित किया गया। साथ ही संभाग स्तरीय बैडमिंटन (महिला) प्रतियोगिता का प्रस्ताव शासकीय कन्या महाविद्यालय द्वारा दिया गया। अन्य सभी आयोजन जिला स्तर पर विभिन्न महाविद्यालय को वितरित किए गए हैं जो शासन द्वारा जारी खेल कैलेंडर के अनुसार विभिन्न तिथियां पर पन्ना जिले के विभिन्न महाविद्यालय में आयोजित किए जाएंगे, बैठक का संपूर्ण संचालन महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी धर्मेंद्र यादव द्वारा किया गया एवं उनके द्वारा अंतिम वर्ष के खेल परिणाम एवं आगामी खेल व्यवस्थाओं हेतू विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस खेल आवंटन बैठक में शासकीय महाविद्यालय खोरा से प्राचार्य डॉ जे के वर्मा, शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ गिरजेश शाक्य एवं क्रीड़ा अधिकारी श्रीमति नाहिद अख्तर, शासकीय गुन्नौर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ, सिद्धू सिंह एवं क्रीड़ा अधिकारी डॉ जितेंद्र कुमार पांडेय ,शासकीय महाविद्यालय अमानगंज से प्राचार्य डॉ पूनम सिंह एवं खेल प्रभारी आरिफ खान, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय देवेन्द्र नगर से प्राचार्य डॉक्टर नीरज शर्मा एवं क्रीड़ा प्रभारी बाबूलाल जमुरा, शासकीय महाविद्यालय देवेंद्र नगर से प्राचार्य डॉ सुखेंद्र गौतम एवं क्रीड़ा अधिकारी अरुण कुमार सिंह, शासकीय महाविद्यालय पवई से क्रीड़ा प्रभारी के.पी. सिंह परमार, शासकीय महाविद्यालय अजयगढ़ से प्राचार्य जेपी अहिरवार एवं क्रीड़ा अधिकारी रवि पाल, शासकीय महाविद्यालय शाह नगर से प्राचार्य डॉक्टर रजनी सोनी उपस्थित रहे।

आभार प्रदर्शन महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी एवं बैठक के संयोजक धर्मेंद्र यादव के द्वारा किया गया।